भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 626

जिसका उत्तर 03 दिसंबर, 2025 को दिया जाना है ।

12 अग्रहायण, 1947 (शक)

एआई एथिकल सर्टिफिकेशन परियोजना

626. डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) प्रेरित शासन और विकास में कार्य बलों के कौशल को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ताकि एआई को तेजी से अपनाने से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों, जिसमें रोजगार के अवसर खोने संबंधी खतरा भी शामिल है, से निपटा जा सके;

(ख) क्या सरकार ने एआई एथिकल सर्टिफिकेशन परियोजना और गोपनीयता सुदृढ़ करने संबंधी रणनीति परियोजना के तहत ऐसे विशिष्ट लक्ष्य और समय-सीमा निर्धारित की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा एथिकल एआई शासन फ्रेमवर्क और मानकों को साथ विकसित करने के लिए किये गए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग या साझेदारी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग)**: भारत की एआई रणनीति, प्रौद्योगिकी के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य भारत-केंद्रित चुनौतियों का समाधान करना, सभी भारतीयों के लिए आर्थिक और रोजगार के अवसर पैदा करना है।

<u>वर्तमान में भारत में एआई इकोसिस्टम:</u>

भारत में एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र है। यह 250 बिलियन डॉलर से अधिक का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है और 6 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स जैसी वैश्विक रैंकिंग भारत को एआई कौशल, क्षमताओं और एआई का उपयोग करने की नीतियों में शीर्ष देशों में रखती है। भारत गिटहब एआई परियोजनाओं में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है, जो अपने जीवंत डेवलपर समुदाय को प्रदर्शित करता है।

<u>भारत की एआई रणनीति:</u>

सरकार ने मार्च 2024 में इंडियाएआई मिशन लॉन्च किया।

यह भारत के विकास लक्ष्यों के साथ एक मजबूत और समावेशी एआई इकोसिस्टम स्थापित करने की एक रणनीतिक पहल है। इसका उद्देश्य एआई-कुशल पेशेवरों का एक मजबूत पूल विकसित करना और देश भर में क्षेत्रीय एआई नवाचार को मजबूत करना है।

1. नाइलिट के सहयोग से टियर-2 और टियर-3 शहरों में 27 इंडियाएआई डेटा और एआई लैब स्थापित किए गए हैं।
    - एआई, डेटा और डेटा एनोटेशन, डेटा क्यूरेशन, डेटा क्लीनिंग, डेटा साइंस आदि जैसे संबंधित क्षेत्रों पर फाउंडेशन-स्तरीय पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

2. 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 174 आईटीआई और पॉलिटेक्निकों को अतिरिक्त इंडियाएआई डेटा और एआई लैब स्थापित करने की मंजूरी दी गई।

3. पीएचडी, स्नातकोत्तर और स्नातक छात्रों के लिए फेलोशिप के माध्यम से एआई क्षमता निर्माण; अब तक 228 से अधिक फेलोशिप प्रदान की गई हैं।

<u>सुरक्षित और विश्वसनीय एआई</u>

यह स्तंभ जिम्मेदार एआई परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सक्षम बनाता है, जिसमें स्वदेशी उपकरणों और ढांचे का विकास, नवप्रवर्तकों के लिए स्व-मूल्यांकन चेकलिस्ट और अन्य दिशानिर्देश और शासन ढांचे शामिल हैं।

एआई प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार विकास, नियोजन और अंगीकरण को सुनिश्चित करने के लिए मजबूत गाडरेल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आठ जिम्मेदार एआई परियोजनाओं का चयन किया गया है।

परियोजनाओं में मशीन अनलर्निंग, सिंथेटिक डेटा जनरेशन, एआई पूर्वाग्रह शमन, नैतिक एआई फ्रेमवर्क, गोपनीयता-बढ़ाने वाले उपकरण, व्याख्यात्मक एआई, एआई गवर्नेंस परीक्षण और एल्गोरिदम ऑडिटिंग टूल सहित कई महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है।

एआई नैतिक प्रमाणन परियोजना

- परियोजना का शीर्षक "निष्पक्ष: एआई मॉडल की निष्पक्षता का आकलन करने के लिए उपकरण" है।
- दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र (टीईसी), दूरसंचार विभाग के सहयोग से आईआईआईटी दिल्ली के नेतृत्व में।
- उद्देश्य: टीईसी के निष्पक्षता मूल्यांकन मानकों के अनुसार एआई मॉडल की निष्पक्षता का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए उपकरण और एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित करना।
- डिलिवरेबल्स में शामिल हैं
    - ओपन-सोर्स निष्पक्षता मूल्यांकन टूलबॉक्स और एपीआई
    - दस्तावेज़ीकरण, परीक्षण ढांचे और रिपोर्ट
- लक्षित उपयोगकर्ताओं में उद्योग, मानक निकाय और सरकारी एजेंसियां शामिल हैं।

गोपनीयता बढ़ाने की रणनीति संबंधी परियोजना

- परियोजना "रोबस्ट प्राइवेसी-प्रिजर्विंग मशीन लर्निंग मॉडल्स" का नेतृत्व आईआईटी दिल्ली द्वारा किया जा रहा है और शैक्षणिक और नियामक भागीदारों (आईआईआईटी दिल्ली, आईआईटी धारवाड़, टीईसी) के एक संघ द्वारा इसे सहयोग दिया गया है।
- इसका उद्देश्य भारतीय वायरलेस और प्रतिकूल वातावरण में नियोजन के लिए उपयुक्त मजबूत, गोपनीयता-संरक्षित वितरित/संघीय शिक्षण विधियों और संबंधित प्रमाणन और परीक्षण प्रक्रियाओं को विकसित करना है।
- संघीय शिक्षा को आगे बढ़ाता है, एक ऐसी तकनीक जो केंद्रीकृत डेटा भंडारण के बिना एआई मॉडल को प्रशिक्षित करती है, साथ ही प्रतिकूल खतरों और संचार चुनौतियों के खिलाफ लचीलापन सुनिश्चित करती है।

भारत ने एआई पर वैश्विक भागीदारी (जीपीएआई) जैसे बहुपक्षीय प्लेटफार्मों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से वैश्विक एआई सहयोग में खुद को सबसे आगे रखा है। इसने पहले परिषद के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, साथ ही 2023 में जी20 अध्यक्षता के दौरान अपने नेतृत्व के माध्यम से भी कार्य किया है।

इसके अलावा, भारत ने समावेशी, न्यायसंगत और नवाचार-अनुकूल एआई शासन को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए फ्रांस के साथ पेरिस एआई एक्शन समिट 2024 की सह-अध्यक्षता भी की।

भारत 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में **भारत-एआई इम्पैक्ट समिट 2026** की मेजबानी करने के लिए तैयार है।

पहली बार, एआई शिखर सम्मेलनों की वैश्विक श्रृंखला ग्लोबल साउथ में आयोजित की जाएगी, जो एक अधिक समावेशी और प्रतिनिधि वैश्विक एआई संवाद की ओर एक निर्णायक बदलाव को दर्शाती है।

शिखर सम्मेलन को सात मुख्य स्तंभों के आसपास संरचित किया गया है, जिसमें सुरक्षित और विश्वसनीय एआई स्तंभ शामिल है, जिसका उद्देश्य जिम्मेदार एआई पद्धतियों को वैश्विक रूप से अपनाने को बढ़ावा देना है।

इंडियाएआई मिशन के तहत, एमईआईटीवाई ने 5 नवंबर 2025 को **इंडियाएआई गवर्नेंस दिशानिर्देश** भी जारी किए हैं । यह व्यापक ढांचा सभी क्षेत्रों में सुरक्षित, समावेशी और जिम्मेदार एआई परिनियोजन की नींव रखता है।

*****